भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या **1975**

जिसका उत्तर शुक्रवार, 2 अगस्त, 2024/11 श्रावण, 1946 (शक) को दिया जाना है।

रबी की फसल के लिए उर्वरकों की मांग और आपूर्ति

1975. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:
श्री रविंद्र दत्ताराम वाइकर:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष में रबी मौसम के दौरान महाराष्ट्र सहित उर्वरक-वार और राज्य-वार विभिन्न उर्वरकों की मांग और आपूर्ति कितनी है;
(ख) क्या महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में किसानों को उर्वरकों, विशेषकर डीएपी और यूरिया की कमी और चालू रबी मौसम के दौरान इसकी आपूर्ति में विलंब के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;
(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के संबंध में तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) आयात के माध्यम से मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है और उनका घरेलू उत्पादन कितना है; और
(ड.) सरकार द्वारा देश में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में जिला-वार क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): कृषि और किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू), प्रत्येक फसल मौसम के शुरू होने से पहले सभी राज्य सरकारों के परामर्श से, सभी उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता/मांग का आकलन करता है। कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित आवश्यकता के आधार पर उर्वरकों को स्वदेशी उत्पादन और आयात के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। रबी मौसम 2024-25 की मांग का आकलन कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा नहीं किया गया है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य सहित देश में उर्वरकों की उपलब्धता चालू खरीफ मौसम 2024 के दौरान सहज है।

(ड.): कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा आकलित उर्वरकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजनाएं जारी करके राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा आवंटित करता है। सभी प्रमुख सब्सिडी प्राप्त उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक निगरानी प्रणाली (आईएफएमएस) नामक वेब आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से की जाती है। तदनुसार, महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों को उर्वरकों की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक विभाग द्वारा उपर्युक्त कदम उठाए गए हैं। तथापि, राज्य के अंदर क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उर्वरकों का अंतर/अन्तःजिला वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

****